**"फूड कारपोरेशन फेसिंग ग्रेन पिलफरेज" समाचार**

*335. **श्री निहाल सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 अप्रैल, 1982 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित "फूड कारपोरेशन फेसिंग ग्रेन पिलफरेज" (खाद्य निगम के खाद्यान्न की चोरी) शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या भारतीय खाद्य निगम के खाद्यान्न की चोरी हो रही है और रेल सुरक्षा बल और स्थानीय पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है क्योंकि उनके क्षेत्राधिकार के संबंध में विवाद है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार पिछले वर्ष कुल कितनी हानि हुई है और क्या विवाद को सुलझा लिया गया है ?

**कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह)** : (क) जी हां। यह समाचार भारतीय खाद्य निगम के सुल्तानपुर लोधी रेलवे स्टेशन (पंजाब) में अप्रैल, 1982 में लदान के लिए भण्डारित स्टाक से खाद्यान्नों की चोरी से संबंधित है।

(ख) और (ग) भारतीय खाद्य निगम के सुल्तानपुर लोधी रेलवे स्टेशन पर लदान के लिए रखे गए स्टाक से खाद्यान्नों की छुट-पुट चोरी के कुछ मामले हुए हैं। रेलवे सुरक्षा बल और स्थानीय पुलिस के बीच क्षेत्राधिकार के बारे में कोई विवाद पैदा नहीं हुआ था। संबंधित क्षेत्र सरकार की रेलवे पुलिस के क्षेत्राधिकार में आता है और इस संबंध में कोई विवाद नहीं है। भारतीय खाद्य निगम ने इस प्रकार की छोटी-मोटी चोरियों को रोकने के लिए अपने स्वयं के सुरक्षा प्रबन्धों में सुधार करने के लिए पग उठाए हैं। क्योंकि छोटी-मोटी चोरी हुई थी, इसलिए पिछले वर्ष के दौरान सुल्तानपुर लोधी स्टेशन पर इसके कारण हुई कुल हानि की राशि नगण्य थी।

**सरकार और अन्य एजेंसियों द्वारा आरम्भ की गई आवास परियोजनाएं**

*336. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि सरकार तथा अन्य एजेन्सियों द्वारा आरम्भ की गई आवास परियोजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की स्थिति में सुधार करने और अपना प्रभाव डालने में विफल रही हैं;

(ख) क्या सरकार ने आवासीय गतिविधियों में बड़ी-बड़ी खामियों की जांच की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में आवासीय और निर्माण परियोजनाओं में सुधार लाने के लिए कौन से प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ?

**संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह)**: (क) सरकार तथा अन्य अभिकरणों द्वारा आरम्भ की गई आवास परियोजनाओं ने देश में आवासीय स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) सरकार ने सर्वदा ही ग्रामीण आवास जनसंख्या के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग तथा अन्य सामाजिक आवास योजनाओं को उच्च प्राथमिकता दी है। छठी पंच वर्षीय योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के सभी शेष 64 लाख भूमिहीन परिवारों को आवास स्थल तथा 36 लाख ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को निर्माण सहायता देने का है। इस योजना की नीति आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के आवास पर बल देना है। इस योजना में हुडको का लगभग 600 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश का विचार है जिस का 55 प्रतिशत आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय वर्ग के आवास के लिए है।

**REQUEST FROM RAJASTHAN FOR ANOTHER STUDY TEAM TO ASSESS DROUGHT RELIEF**

*338. SHRI KRISHNA KUMAR GOYAL : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that Rajasthan Government have requested the Centre to send a second team to the State to make a realistic assessment of its financial requirements for drought relief and asked